राजस्थान राज्य

बनाम

दिनेश कुमार भारती

20 जनवरी, 1997

[न्यायमूर्ति, के0 रामास्वामी और न्यायमूर्ति, जी0 टी0 नानावती]

सेवा कानून:

राजस्थान सेवा नियम, 1951:

नियम 6(बी)(3)234, 25 –शिक्षकों की तदर्थ नियुक्ति –स्क्रीनिंग कमेटी ने प्रतिवादी को स्थायीकरण के योग्य नहीं पाया –सेवा समाप्ति –ट्रायल कोर्ट द्वारा आदेश और अपीलीय न्यायालय द्वारा पुष्टि, उच्च न्यायालय ने दूसरे को खारिज करते हुए सीमा के आधार पर अपील की गई अपील पर, जहां लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श आवश्यक है, लेकिन पुष्टि के योग्य नहीं पाया गया, लिखित में तीन महीने का नोटिस आवश्यक है, प्रतिवादी के मामले में, सहमति की आवश्यकता नहीं है, इसलिए नीचे के न्यायालयों का दृष्टिकोण स्पष्ट था गलत–उच्च न्यायालय द्वारा देरी के आधार पर अपील खारिज करना सही नहीं है।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 349/1997

राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 4.11.92 को एस.ए. संख्या 175/1992 में पारित निर्णय और आदेश से।

अरुणेश्वर गुप्ता, अपीलकर्ता की ओर से

इंद्रा मकवाना, प्रतिवादी की ओर से

न्यायालय द्वारा निम्नलिखित आदेश दिया गया:

अनुमति प्रदान की गई

हमने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया।

यह अपील, विशेष अनुमति से सिंगल जज, राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा एस0ए0 संख्या 175/1992 मे पारित आदेश दिनांक 4, नवम्बर, 1992 के विरूद्ध दायर की गयी। विद्वान न्यायाधीश ने परिसीमा के आधार पर दूसरी अपील खारिज कर दी। दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओ को सुनने के बाद, हमें लगता है कि मामले को दोबारा भेजने के बजाय गुण–दोष के आधार पर इसका

निपटारा किया जा सकता है। प्रतिवादी को 30 सितंबर, 1970 को तदर्थ आधार पर एक शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। तदर्थ शिक्षकों की सेवाओं को नियमित करने के लिए गठित स्क्रीनिंग कमेटी ने पाया कि प्रतिवादी स्थायीकरण के लिए उपयुक्त नहीं है। इसके आधार पर 8 मई, 1974 को बर्खास्तगी का आदेश दिया गया। इसे मुकदमे में चुनौती दी गई। अंततः, जब ट्रायल कोर्ट द्वारा इस पर फैसला सुनाया गया और अपीलीय न्यायालय द्वारा इसकी पुष्टि की गई, तो उच्च न्यायालय ने परिसीमा के आधार पर दूसरी अपील खारिज कर दी। जिला न्यायाधीश ने राजस्थान सेवा नियम, 1951 के नियम 23 ए पर भरोसा करते हुए कहा कि सेवा समाप्त करने के लिए नियम 23 ए के तहत आवश्यक पूर्व सूचना नहीं दी गई थी। इसलिए कानून की नजर में यह आदेश खराब है. नियमों का नियम 6(बी), (3) इस प्रकार प्रदान करता है:

> "नियम 6(बी)(3) – जो व्यक्ति 31.12.72 को निर्धारित अनुभाग बी, सी, डी, ई और एफ या अनुभाग "ए" में निम्नलिखित ग्रेड । पद में से किसी एक पद को धारण करता है। एक तदर्थ/स्थानापन्न/अस्थायी क्षमता वाला व्यक्ति और जिसने 15–12–1971 को कम से कम छह महीने की अवधि के लिए उक्त पद को लगातार धारण किया हो या अन्यत्र प्रतिनियुक्ति के अलावा इनमें से किसी भी पद पर कार्य करता हो और इस पर काम कर रहा हो। इन (संशोधन) नियमों के प्रकाशन की तारीख की जांच नियम 25 में निर्दिष्ट एक समिति द्वारा की जाएगी, ताकि ऐसे पद के लिए उसकी उपयुक्तता का फैसला किया जा सके, बशर्ते कि उसके पास सीधी भर्ती या पदोन्नति के लिए नियमों में निर्धारित योग्यता या निर्धारित योग्यता हो। वे पद जिनके आधार पर उन्हें ऐसे पद पर तदर्थ या स्थानापन्न या अस्थायी क्षमता में नियुक्त किया गया था।"

नियम 25 के तहत, नियमितीकरण के लिए तदर्थ शिक्षकों की उपयुक्तता का निर्णय करने के लिए स्क्रीनिंग कमेटी नियुक्त की गई थी। उपरोक्त नियम के परिणामस्वरूप, स्क्रीनिंग कमेटी ने अस्थायी या स्थानापन्न आधार पर या तदर्थ क्षमता में पद धारण करने वाले व्यक्तियों पर विचार किया, जो 15 दिसंबर, 1971 को कम से कम छह महीने की अवधि के लिए लगातार पद पर थे और इस तरह काम कर रहे थे। नियमों में संशोधन के प्रकाशन की तिथि पर. पदों के लिए उनकी उपयुक्तता का निर्णय करने के लिए नियम 25 के तहत गठित एक समिति द्वारा उनकी जांच की जानी आवश्यक थी, बशर्ते कि उनके पास सीधी भर्ती या पदोन्नति के लिए नियम के तहत निर्धारित योग्यता या पदों की निर्धारित योग्यता हो, जिसके आधार पर वे तदर्थ या स्थानापन्न या अस्थायी क्षमता में नियुक्त किए गए थे। माना जाता है कि समिति का गठन 1974 में नियम 25 के तहत किया गया था और समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची कि प्रतिवादी पुष्टि के लिए उपयुक्त नहीं है। नियम 23 ए 10 जुलाई 1981 से लागू किया गया था। नियम 23 ए(2) इस प्रकार है:

> "एक अस्थायी सरकारी कर्मचारी की सेवा जो तीन वर्ष से अधिक समय से लगातार सरकारी सेवा में है और जो पद के लिए निर्धारित आयु और योग्यता के संबंध में उपयुक्तता को पूरा करता है और राजस्थान लोक सेवा आयोग के परामर्श से नियुक्त किया गया है जहां ऐसा उत्तरदायी है किसी भी समय सरकारी सेवक द्वारा नियुक्ति प्राधिकारी को या नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सरकारी सेवक को लिखित रूप में तीन महीने का नोटिस देकर समाप्त किया जा सकता है।

> बशर्ते कि ऐसे किसी भी सरकारी कर्मचारी की सेवा तुरंत समाप्त की जा सकती है, और ऐसी समाप्ति पर सरकारी कर्मचारी नोटिस की अवधि के लिए अपने वेतन और भत्ते की राशि के बराबर राशि का दावा उसी दर पर करने का हकदार होगा जिस दर पर वह था। उसकी सेवा की समाप्ति से तुरंत पहले उस अवधि के लिए आहरण, जिसमें ऐसा नोटिस तीन महीने से कम हो जाता है, जैसा भी मामला हो।"

इसलिए, नियम 23(2)(ए) स्वयं लागू नहीं था। अन्यथा भी, यह मानते हुए कि यह लागू था, यह दुखद है कि यह ऐसे मामले में लागू होगा जहां लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श आवश्यक है और लोक सेवा आयोग सरकारी कर्मचारी को स्थायी किए जाने के योग्य नहीं पाता है। ऐसे मामले में तीन माह का लिखित नोटिस देने पर ही सेवा समाप्ति की जा सकेगी। इस मामले में स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया गया. यह स्पष्ट रूप से धारा 23 ए के तहत एफ के लिए लोक सेवा आयोग की सहमति प्राप्त करने वाला मामला नहीं है। उन परिस्थितियों में, नीचे की अदालतों का दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से गलत था। उच्च न्यायालय द्वारा देरी के आधार पर अपील खारिज करना गलत था।

तदनुसार अपील स्वीकार की जाती है। जी के नीचे की अदालतों का आदेश रद्द किया जाता है। कोई लागत नहीं।

जी.एन.

अपील स्वीकार की जाती है।

Sandeep Kumar Jaiswal, Advocate

Enrollment No.UP-5956/2018

AOR No.A/S-0328/2019

Sandeep